RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 29 JUNE 2022 TO 05 JULY 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 42 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

रूस से तेल आयात की मूल्य सीमा पर भारत समेत अन्य देशों से गहन बातचीत हुई: अमेरिका

Page 2

अप्रैल-जून में आठ शहरों में आवास बिक्री में 4.5 गुना वार्षिक वृद्धि :रिपोर्ट

Page 4

शरीर में सामान छिपाकर ले जाने वालों के लिए फुल बॉडी स्केनर

Page 5

editoria!

डिजिटल अर्थव्यवस्था

मौजूदा दौर में आर्थिक सुधारों का मुख्य आधार प्रौद्योगिकी आधारित विकास है. इसे देखते हुए सरकार ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा, ड्रोन और भू-स्थानिक डेटा जैसे अनेक क्षेत्रों में नवाचार अनुकूल नीतियां बनायी हैं. ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में हो रहे अभूतपूर्व डिजिटल परिवर्तन को दुनिया देख रही है. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की क्षमता 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की है. देश में 70,000 स्टार्टअप आये हैं, जिसमें 100 से अधिक तो यूनिकॉर्न बने हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है. इस प्रगति को देखते हुए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश का अवसर बन सकता है. इस प्रकार, भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक एक ट्रिलियन के आंकड़े को छू सकती है. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का असर न केवल आर्थिकी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी हो रहा है. डिजिटल अर्थव्यवस्था के तहत डिजिटल पेमेंट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी मुहिम लाखों भारतीयों के जीवन में बदलाव ला रही है. मोबाइल यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए अनुमान है कि 2025 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट बन जायेगा. डिजिटल संस्कृति के विकास से ई-कॉमर्स और व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों में तेजी आयी है. बढ़ते मध्य वर्ग, युवा, टेक-सैवी आबादी और ऑनलाइन व्यक्तिगत सेवाओं में बढ़त ने संभावनाओं के फलक को और बढ़ाया है. इससे वैश्विक कंपनियां निवेश के लिए प्रेरित होंगी, तो वहीं डिजिटल कौशल युक्त युवा आबादी के लिए मौके भी बनेंगे. इससे देश के साथ-साथ वैश्विक मांग को भी वे अपने पक्ष में कर सकेंगे. हालांकि, डिजिटल अवसंरचना विकास के लिए कार्ययोजना और निवेश दोनों पर समानांतर पहल जरूरी है. डिजिटल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एस्टोनिया ने उच्च-प्रौद्योगिकी अवसंरचना विकास पर जोर दिया, जिससे वह यूरोप का डिजिटल लीडर बन गया. वहीं कुछ यूरोपीय देश प्रतिस्पर्धा से बचते रहे. भारत को ऐसी नीतियों पर काम करने की जरूरत है, जो पूरी अर्थव्यवस्था के हित में हो. डिजिटलीकरण की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं, मसलन, असमान इंटरनेट पहुंच, मोबाइल स्वामित्व में लैंगिक अंतर, नेटवर्क और साइबर सुरक्षा के प्रश्न पर हमें गौर करना होगा. डिजिटल क्रांति में उन समुदायों और इलाकों को भी जोड़ने की आवश्यकता है, जो सूचना और प्रौद्योगिकी विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गये हैं. अधिकाधिक डिजिटल लाभ के लिए मुख्य तौर पर तीन प्रमुख क्षेत्रों- डिजिटल प्रतिस्पर्धा, नवाचार और उद्यमिता पर फोकस करने की आवश्यकता है. सस्ती, विकासात्मक और समावेशी डिजिटल प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित होगी. ऐसे बदलावों से विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़ेगा. साथ ही, डिजिटल नवाचार का सबसे बड़ा पावरहाउस बनकर उभरेगा.

होटल में रुकना अब होगा महंगा, दही-पनीर सहित कई पैकेज्ड फूड्स की भी बढ़ेंगी कीमतें

जानिए कितना असर डालेगी जीएसटी की महंगाई

नयी दिल्ली। एजेंसी

पहले से ही महंगाई से जूझ रहे लोगों पर कीमतों का बोझ और बढ़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल की चंडीगढ़ में चल रही बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये जा रहे हैं। कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा हुई है और कुछ पर चर्चा चल रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक का बुधवार को दूसरा दिन है। बैठक के पहले दिन मंगलवार को दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल-युक्त या ब्रांडेड चीजों पर जीएसटी लगाने का फैसला हुआ है। इससे अब इन वस्तुओं के लिए ग्राहकों को अधिक रकम चुकानी होगी। इसके अलावा अब होटल में रुकना, बैकिंग और एजुकेशन में भी जीएसटी की महंगाई देखने को मिलेगी। जीएसटी की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद थे। इस बैठक में इन वित्त मंत्रियों की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। आइए जानते हैं कि जीएसटी दरों में बदलाव का लोगों पर क्या असर पड़ेगा।

होटल में रुकना होगा महंगा

अगर आप अक्सर होटल्स में रुकते हैं, तो आपकी जेब पर बोझ अब बढ़ने वाला है। अब एक हजार रुपये रोजाना से कम किराए वाले होटल रूम पर 12 फीसद की दर से जीएसटी लगेगा। अभी तक इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। इस तरह अब आपका होटल में रुकना महंगा होने वाला है। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरों (आईसीयू को छोड़कर) पर पांच फीसद जीएसटी लगाने की भी सिफारिश की गई है।

महंगे होंगे डिब्बा बंद उत्पाद

दही, पनीर, शहद और मांस-मछली जैसे उत्पाद अगर ब्रैंडेड या डिब्बा बंद हैं, तो उन पर अब जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने इन ब्रैंडेड या लेबल युक्त वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला लिया है। अब इन वस्तुओं पर पांच फीसद जीएसटी लगेगा।

यह बैंकिंग काम होगा महंगा

अब चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिये जाने वाला शुल्क भी जीएसटी के दायरे में आएगा। जीएसटी काउंसिल ने मंगलवार को यह फैसला लिया है। चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा।

स्टूडेंट्स के ये सामान हो जाएंगे महंगे

अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अब आपको कुछ सामानों के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। जीएसटी काउंसिल ने चार्ट पेपर और एटलस नक्शे पर 12 फीसद जीएसटी लगाने का फैसला किया है। हालांकि, ये गैर ब्रैंडेड हैं और खुले में बिक रहे हैं, तो जीएसटी छूट जारी रहेगी।

ये उत्पाद हो जाएंगे महंगे

दही, पनीर, शहद और मांस-मछली जैसे ब्रैंडेड या डिब्बा बंद उत्पाद 5%
1,000 रुपये से कम का होटल रूम 12%
चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाला शुल्क 18%
पढ़ाई में काम आने वाले चार्ट पेपर व एटलस नक्शे 12%

सोना और कीमती पत्थर हो सकते हैं महंगे

जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए ई-वे बिल जारी करने की राज्यों को मंजूरी दी है। इससे इन सामानों की कीमतों में कुछ तेजी आ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में इस समय जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक चल रही है। बुधवार को इस बैठक का दुसरा व आखिरी दिन है। जीएसटी काउंसिल बुधवार को राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये क्षतिपूर्ति व्यवस्था जून, 2022 के बाद भी जारी रखने की मांग पर विचार कर सकती है। इसके अलावा कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28 फीसद जीएसटी लगाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ जैसे विपक्ष-शासित राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को पांच साल के लिए बढ़ाने या राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी मौजूदा 50 फीसद से बढ़ाकर 70-80 फीसद करने की मांग कर रहे हैं।

राज्यों की कारोबार सुगमता रैंकिंग जारी होगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कारोबारी सुगमता के मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग 30 जून को जारी की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कारोबार सुधार कार्रवाई योजना (बीआरएपी), 2020 के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन बृहस्पतिवार को पेश करेंगी। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। इस कवायद का उद्देश्य राज्यों के बीच व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है जिससे कि वे घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर सकें। बीआरएपी-2020 में 301 सुधार बिंदु शामिल हैं, जिसके तहत 15 कारोबार नियामकीय क्षेत्र आते हैं। इनमें सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम, पर्यावरण और अन्य सुधार आदि। उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) बीआरएपी के तहत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2014 से यह रैंकिंग तैयार करता आया है। पिछली रैंकिंग सितंबर, 2020 में जारी की गई थी जिसमें आंध्र प्रदेश को कारोबारी सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला था। उसके बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड थे। यह रैंकिंग वर्ष 2015, 2016, 2017-18 और 2019 के लिए जारी की जा चुकी है।

रूस से तेल आयात की मूल्य सीमा पर भारत समेत अन्य देशों से गहन बातचीत हुई: अमेरिका

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका ने कहा है कि उसने भारत समेत प्रमुख तेल उपभोक्ता देशों के साथ इस विषय पर गहन चर्चा की है कि रूस से होने वाले तेल आयात पर मूल्य सीमा किस तरह तय की जा सकती है। हालांकि, हाल में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस विषय में कोई बात नहीं हुई है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के समूह जी-7 के नेताओं ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान में कहा था कि रूस की तेल बिक्री से होने वाली आय को रोकने के लिए वे दूरगामी कदम उठाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि नेताओं ने मंत्रियों से कहा है कि इस दिशा में काम किस तरह हो सकता है उसके तरीके खोजे जाएं।

उनसे सवाल किया गया कि क्या जी-7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत द्वारा रूस से तेल खरीद के बारे में कोई बात हुई है। इस पर सुलिवन ने कहा, ''इसका एक पहलू है तेल की खपत करने वाले प्रमुख देशों से बातचीत। भारत उनमें से एक है। बातचीत शुरू हो चुकी है।'' सुलिवन ने कहा, ''हमने भारत से इस बारे में बात की है कि कीमतों की सीमा किस तरह तय की जा सकती है और इसके क्या प्रभाव होंगे।''

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी-7 सम्मेलन के दौरान बाइडन ने रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर मोदी से कोई बात नहीं की है। उन्होंने कहा, ''अमेरिकी सरकार में वरिष्ठ स्तर से हमने भारतीयों से सोमवार को इस बारे में बात की है। इस विषय में नेताओं के स्तर तक जाने से पहले हमें कैबिनेट स्तर

पर उनकी टीम के साथ विस्तार से काम करना होगा, इसके बाद जरूरत पड़ी तो इसे आगे के स्तर तक ले जाया जाएगा।''

घरेलू कच्चा तेल उत्पादकों को अपनी मर्जी से बिक्री की अनुमति

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने बुधवार को देश में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को विपणन के मामले में पूरी छूट देने का निर्णय किया। उन्हें अपनी इच्छानुसार तेल बेचने की अनुमति दी गयी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को दी जानकारी में कहा कि मंत्रिमंडल ने घरेलू बाजार में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण-मुक्त करने की मंजूरी दी है। इसके तहत, एक अक्टूबर से उत्पादन भागीदारी अनुबंध (पीएससी) में कच्चा तेल सरकार या उसके द्वारा नामित इकाइयों अथवा सरकारी कंपनियों को बेचने की शर्त समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि उत्पादक अपने क्षेत्रों से उत्पादित कच्चा तेल घरेलू बाजार में बेचने को स्वतंत्र होंगे।

विकसित देशों की मंदी भारत के लिए बन सकती है वरदान

नई दिल्ली। एजेंसी

पूरी दुनिया मंदी की आहट से सहमी हुई है। अमेरिका सहित कई विकसित देशों में मंदी की आशंका हर बीतते दिन के साथ भयावह होती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अमेरिकन इकॉनमी की ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 2.9 फीसदी कर दिया है। उसका कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी के मंदी से बचने के आसार दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में मंदी भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। उनका तर्क है कि विकसित देशों में मंदी से दुनियाभर में कमोडिटीज की कीमतों में कमी आएगी। इससे भारत में महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। सिटीग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और भारत में इसके चीफ इकनॉमिस्ट समीरन चक्रवर्ती ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत कमोडिटीज का नेट इम्पोर्टर है। इसलिए विकसित देशों में मंदी से भारत को महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलनी चाहिए। लेकिन भारत को भी वैश्विक मंदी के कारण दबाव का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि इससे एक्सपोर्ट प्रभावित होगा और इकनॉमिक ग्रोथ में कमी आएगी। इस समय देश के नीति निर्माताओं का जोर महंगाई को काबू करने पर है। इसलिए कहा जा सकता है कि मंदी भारत के लिए कुछ मायनों में फायदेमंद हो सकती है।

रेपो रेट में इजाफा

पूरी दुनिया में मंदी की आशंका जोर पकड़ रही है। महंगाई को काबू में करने के लिए दुनियाभर के देशों के केंद्रीय बैंकों ने प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई और महामारी के दौर में उठाए गए राहत के कदमों को वापस लिए जाने के कारण महंगाई चरम पर है। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई विकसित देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। आरबीआई भी मई के ब्याज दरों में 90 फीसदी इजाफा कर चुका है।

जानकारों का कहना है कि इसमें अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि महंगाई आरबीआई की तय सीमा से कहीं अधिक स्तर पर बनी हुई है। चक्रवर्ती ने कहा कि अगर महंगाई काबू में नहीं आती है तो आरबीआई रेपो रेट को छह फीसदी तक ले जा सकता है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने हाल में कहा था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई अगली तीन तिमाहियों तक आरबीआई के सीमा से ऊपर बनी रह सकती है। आरबीआई ने इसके लिए दो से छह फीसदी की टारगेट रेंज रखी है।

मई में क्रेडिट कार्ड के जरिये 1.13 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

मुंबई। एजेंसी

देश में मई के दौरान क्रेडिट कार्ड से भुगतान बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया, जो एक महीने पहले यानी अप्रैल में 1.05 लाख करोड़ रुपये था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, मासिक आधार पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है। रिजर्व बैंक ने बताया कि आलोच्य माह के दौरान 7.68 करोड़ क्रेडिट कार्डधारकों ने ऑनलाइन माध्यम से सामान खरीदने के लिए 71,429 करोड़ रुपये का भुगतान किया। जबकि पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के जरिये कार्ड स्वाइप करके 42,266 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं, क्रेडिट कार्ड के जरिये ऑनलाइन भुगतान के लेन-देन की मात्रा मई में 11.5 करोड़ रही, जो ऑफलाइन या पीओएस मशीने के जरिये 12.2 करोड़ थी। आंकड़ों के अनुसार, यह रुख दर्शाता है कि क्रेडिट कार्डधारक ऑफलाइन माध्यम की तुलना में ऑनलाइन मंचों के जरिये औसतन अधिक मूल्य के लेनदेन कर रहे हैं। क्रेडिट कार्डधारकों ने ऑनलाइन खरीदारी पर अप्रैल के दौरान 65,652 करोड़ रुपये जबकि पीओएस मशीनों के जरिये 39,806 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसके अलावा मई के दौरान 20 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी हुए। अप्रैल में क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या 7.51 करोड़ थी। रिजर्व बैंक के मार्च में नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध हटाने के बाद एचडीएफसी बैंक के पास मई में सबसे अधिक 1.72 करोड़ क्रेडिट कार्ड थे।

मुंबई हवाईअड्डे पर घरेलू, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए साझा सुरक्षा जांच चौकी स्थापित

मुंबई। एजेंसी

अडाणी समूह के नियंत्रण वाले मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए साझा सुरक्षा जांच चौकी स्थापित की है। इसके अलावा हवाईअड्डे की नयी साझा सुरक्षा जांच चौकी पर 13 रोलर और सेंसर-आधारित स्वचालित ट्रे रिट्रीवल सिस्टम (एटीआरएस) स्थापित किए गए हैं, जो यात्रियों के प्रसंस्करण समय को और आसान बनाएगा। परिचालक कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने टर्मिनल से प्रस्थान करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल1 पर एटीआरएस स्थापित करने की भी योजना बनाई है। गौरतलब है कि मुंबई हवाईअड्डे पर टी1 और टी2 दो टर्मिनल है। इसमें टी1 घरेलू और टी2 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए है। बयान के अनुसार, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के टी2 से प्रस्थान करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री साझा सुरक्षा जांच चौकी से गुजरेंगे, जो देश में पहली बार किसी हवाईअड्डे पर होगा।

अदाणी समूह ने कच्छ कॉपर लिमिटेड प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोजर प्राप्त किया

अहमदाबाद। आईपीटी नेटवर्क

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड एईएल की सहायक कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड केसीएल ने दो चरणों में 1 एमटीपीए मिलियन टन प्रतिवर्ष के साथ रिफाइंड कॉपर के उत्पादन के लिए एक ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। 0.5 एमटीपीए की चरण 1 क्षमता के लिए, केसीएल ने मुंद्रा, गुजरात में ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए सिंडिकेटेड क्लब लोन के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के साथ वित्तपोषण दस्तावेजों के निष्पादन के साथ फाइनेंशियल क्लोजर हासिल किया है। इसमें अन्य कंसोर्टियम सदस्यों में बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं। बैंकों के संघ ने केसीएल परियोजना के चरण 1 के लिए 6071 करोड़ रुपये की संपूर्ण ऋण आवश्यकता के लिए स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए हैं। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डायरेक्टर श्री विनय प्रकाश ने कहा, 'आत्मनिर्भर भारत' के साथ गठबंधन करते हुए, केसीएल का लक्ष्य रिफाइंड कॉपर के उत्पादन की क्षमता बनाना है, जो ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर देश के बदलाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और साइट पर निर्माण कार्य अच्छी तरह से प्रगति पर है और सीवाय 2024 की पहली छमाही के दौरान उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। यह बेंचमार्क ईएसजी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े कॉपर रिफाइनरी परिसरों में से एक होगा, जो आर्ट टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण में राज्य की स्थिति का लाभ उठाएगा। यह फाइनेंशियल क्लोजर हमें प्रोजेक्ट में तेजी लाने में सक्षम बनाता है और आवश्यक संसाधन जुटाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अदाणी समूह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कच्छ कॉपर लिमिटेड अदाणी पोर्टफोलियो के मैटेरियल्स, मेटल्स और माइनिंग वर्टिकल का हिस्सा होगा।'

एएससीआई वार्षिक शिकायत रिपोर्ट 2021-22

स्व-नियामक निकाय के रूप में डिजिटल माध्यम पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही आपत्तिजनक विज्ञापनों में कुल मिलाकर 62% की वृद्धि

सबसे बड़े उल्लंघनकारी क्षेत्र में शिक्षा है, इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल और व्यक्तिगत देखभाल है

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

एडवर्टाइज़िंग स्टैंडर्ड्स काउन्सिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने 21 अप्रैल से 22 मार्च की अवधि के लिए अपनी वार्षिक शिकायत रिपोर्ट जारी की, जिसके दौरान कंपनी ने प्रिंट, डिजिटल और टेलीविजन सहित सभी माध्यमों में 5,532 विज्ञापनों को संसाधित किया। डिजिटल डोमेन पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, एएससीआई द्वारा 94% समग्र अनुपालन दर देखी गई। वर्ष 2021-22 में, एएससीआई ने पिछले वर्ष की तुलना में 62% अधिक विज्ञापनों और 25% अधिक शिकायतों को संसाधित किया। जबकि टेलीविजन और प्रिंट विज्ञापन फोकस में रहे, एएससीआई ने डिजिटल परिदृश्य में विज्ञापन को लगातार निगरानी में रखकर अपने दायरे को व्यापक बनाया। संसाधित किए गए विज्ञापनों में से लगभग 48३ डिजिटल माध्यम से संबंधित थे। पिछले वर्ष प्रभावशाली दिशा-निर्देशों के लागू होने के साथ ही साथ, प्रभावशाली लोगों के खिलाफ शिकायतें, कुल शिकायतों की 29% थीं। वहीं मशहूर हस्तियों वाले विज्ञापनों में भ्रामक दावों की शिकायतों में 41% की वृद्धि देखी गई, जिनमें से 92% को एएससीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। डिजिटल निगरानी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, उभरती श्रेणियों में आभासी डिजिटल संपत्ति और ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग की अपेक्षाकृत नई श्रेणियाँ शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 8% आपत्तिजनक विज्ञापनों में महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा (33%), स्वास्थ्य देखभाल (16%) और व्यक्तिगत देखभाल (11%) शीर्ष 3 उल्लंघनकारी श्रेणियाँ थीं।

वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए, सुभाष कामथ, चेयरमैन, एएससीआई, ने कहा, 'जिस तरह से यह विज्ञापन परिदृश्य पर हावी है, वर्ष 2021-22 एक ऐसा वर्ष था, जब हमने डिजिटल मीडिया की निगरानी में तेजी लाने के अपने वादे का पालन किया। हमने प्रौद्योगिकी में भारी निवेश किया है और यह काफी अच्छा परिणाम हमारे सामने लेकर आया है। वार्षिक रिपोर्ट के बारे में अपने विचार साझा करते हुए, मनीषा कपूर, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल, एएससीआई, ने कहा, 'एएससीआई टीम, उपभोक्ता शिकायत परिषद्, हमारे समीक्षा पैनल में माननीय पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हमारे डोमेन विशेषज्ञों ने इसकी बारीकियों पर गहन चर्चा की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया और परिणाम उपभोक्ताओं और विज्ञापनदाताओं दोनों के ही लिए उचित हैं।

जीएसटी बैठक के दूसरे दिन राज्यों को क्षतिपूर्ति

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी कर पर होगी बात

चंडीगढ़। जीएसटी परिषद की चंडीगढ़ में मंगलवार को शुरू हुई बैठक के दूसरे दिन राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को जारी रखने और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो तथा घुड़दौड़ पर सर्वाधिक 28 फीसदी की दर से कर लगाने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। बैठक के पहले दिन, मंगलवार को जीएसटी परिषद ने कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरों में बदलाव को मंजूरी दी थी।

दूसरे दिन, राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति को जून 2022 के बाद विस्तार देना और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो तथा घुड़दौड़ पर 28 फीसदी कर लगाने की एक मंत्री समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर बात होगी। मंत्री समूह ने इन गतिविधियों के लिए एक समान कर दर और मूल्यांकन प्रक्रिया का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि जीएसटी लगाने के उद्देश्य से, इन गतिविधियों में केवल इस आधार पर कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए कि कोई गतिविधि कौशल या संयोग या दोनों का खेल है। जीओएम का कहना है कि प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क समेत ऑनलाइन गेमिंग के पूरे मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए। रेसकोर्स के मामले में भी मंत्री समूह ने दांव के पूरे मूल्य पर जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। मंत्री समूह ने कहा है कि कसीनो में भी खिलाड़ी द्वारा खरीदे गए कुल सिक्कों के पूरे अंकित मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए।

जीएसटी परिषद ने कसीनो, लॉटरी पर कर लगाने के बारे में निर्णय टाला

चंडीगढ़। एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने कसीनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी पर 28 प्रतिशत कर लगाने के निर्णय को टाल दिया है। इसका कारण यह है कि संबंधित पक्षों के साथ अभी और विचार-विमर्श करने की जरूरत है। सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) से मूल्यांकन प्रणाली पर संबंधित पक्षों के प्रतिवेदनों पर फिर से विचार करने और अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई तक देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के लिये परिषद की बैठक अगस्त के पहले सप्ताह में होगी। परिषद की दो दिन की बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट पर विचार किया गया लेकिन निर्णय टाल दिया गया। इसका कारण गोवा और कुछ अन्य राज्य इस बारे में अपने और सुझाव रखना चाहते हैं।जीओएम ने 'ऑनलाइन गेमिंग' के मामले में उसके पूरे मूल्य के आधार पर कर लगाने की सिफारिश की थी। इसमें खिलाड़ियों के खेल में भाग लेने के लिये प्रवेश शुल्क शामिल है। घुड़दौड़ के मामले में दांव पर लगी पूरी राशि के मूल्य के आधार पर जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया था। जीओएम ने इन चीजों पर 28 प्रतिशत की ऊंची दर से कर लगाने की सिफारिश की थी।

डॉलर के मुकाबले रुपये में सबसे बड़ी गिरावट, पहली बार 79 के लेवल के नीचे फिसला रुपया

मुंबई। डॉलर के मुकाबले रुपये में बुधवार को पहली बार 79 रुपये के नीचे जा फिसला है। करेंसी मार्केट में आज का कारोबार खत्म होने पर रुपये में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली और एक डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 19 पैसे गिरकर 79.04 रुपये पर क्लोज हुआ है। रुपया पिछले छह दिनों से लगातार रिकॉर्ड निचले स्तरों पर क्लोज हो रहा है। दरअसल कच्चे तेल के दामों में उछाल, महंगाई में तेज और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते रुपया में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले 78.86 पर खुला था लेकिन फिर 79.04 के निचले स्तरों तक जा लुढ़का है। इस वर्ष रुपया 5.8 फीसदी से ज्यादा नीचे फिसल चुका है। बता दें 23 फरवरी, 2022 को युद्ध शुरू होने से पहले रुपया डॉलर के मुकाबले 74.62 रुपये पर था। जानकारों का मानना है कि रुपये डॉलर के मुकाबले 80 रुपये के लेवल तक गिर सकता है।

दरअसल विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते करेंसी मार्केट में डॉलर की कमी तेजी जा रही है। जबकि डॉलर की मांग बढ़ी है। विदेशी निवेशकों ने इस वर्ष भारतीय बाजार में 28 अरब डॉलर का अपना निवेश वापस निकाल लिया है। आरबीआई ने कहा था कि वो अपने रिजर्व से मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहा है।

वहीं अमेरिकी फेड रिजर्व जुलाई में फिर से ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले सकता है। इस डर से विदेशी निवेशक बिकवाली कर अपना पैसा निकालने में जुटे हैं। बहरहाल डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट भारत की मुसीबत बढ़ा सकता है क्योंकि ईंधन से लेकर खाने के तेल जैसी चीजें महंगी हो सकती है।

अप्रैल-जून में आठ शहरों में आवास बिक्री में 4.5 गुना वार्षिक वृद्धि :रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान आठ शहरों में आवास बिक्री सालाना आधार पर 4.5 गुना बढ़कर 74,330 इकाई पर पहुंच गई। वहीं आवासों की मांग जनवरी-मार्च की पिछली तिमाही की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक रही। संपत्ति सलाहकार प्रॉपटाइगर के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। पिछले साल अप्रैल-जून की अवधि में 15,968 आवास बिके थे और 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में यह आंकड़ा 70,623 इकाई था।

ऑस्ट्रेलिया के आरईए समूह के स्वामित्व वाली प्रॉपटाइगर डॉट कॉम ने अपनी नवीनतम 'रियल इनसाइट रेजिडेंशियल' रिपोर्ट में कहा कि अप्रैल-जून, 2022 में सालाना वृद्धि कई गुना रही है क्योंकि पिछले साल की समान अवधि में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आवासीय मांग गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक, अहमदाबाद में आवास की बिक्री इस साल की अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर 7,240 इकाई पर पहुंच गई, जो एक साल पहले की अवधि में 1,280 इकाई थी। इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में बिक्री 5,550 इकाई रही थी और हाल के बिक्री आंकड़े इससे 30 फीसदी अधिक हैं। बेंगलुरु में अप्रैल-जून के दौरान आवास की बिक्री पिछली तिमाही की तुलना में नौ प्रतिशत बढ़कर 8,350 इकाई पर पहुंच गई। पिछली तिमाही में 7,670 इकाइयां बिकी थी। जबकि एक साल पहले की अवधि में केवल 1,590 इकाइयों की बिक्री हुई थी। चेन्नई में आवास की बिक्री अप्रैल-जून, 2022 में बढ़कर 3,220 इकाई हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 710 इकाई थी। हालांकि, हाल की बिक्री जनवरी-मार्च, 2022 की 3,300 इकाइयों से दो प्रतिशत कम रहीं।

दिल्ली-एनसीआर के बाजार में इस साल अप्रैल-जून के दौरान बिक्री 60 प्रतिशत बढ़कर 4,520 इकाई पर पहुंच गई, जो एक साल पहले की अवधि में 2,830 इकाई थी। पिछली तिमाही में बिक्री 5,010 इकाई थी। अप्रैल-जून 2022 में आवासीय संपत्तियों की बिक्री बढ़कर 7,910 इकाई पर पहुंच गई, जो एक साल पहले की अवधि में 2,430 इकाई थी। यह जनवरी-मार्च 2022 में बिकीं 6,560 इकाइयों की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। कोलकाता में, बिक्री अप्रैल-जून 2022 के दौरान दोगुनी से अधिक 3,220 इकाई पर पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,250 इकाई थी। यह 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में बिकीं 2,860 इकाइयों से 13 प्रतिशत अधिक थी। मुंबई में आवास की बिक्री अप्रैल-जून 2022 के दौरान कई गुना बढ़कर 26,150 इकाई हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में केवल 3,380 इकाई थी। यह पिछली तिमाही में बिकीं 23,360 इकाइयों से 12 प्रतिशत अधिक थी। पुणे में अप्रैल-जून 2022 में 13,720 इकाइयों की बिक्री हुई, जबकि एक साल पहले की अवधि में 2,500 इकाइयों की बिक्री हुई थी। यह जनवरी-मार्च 2022 में बिकीं 16,310 इकाइयों से 16 प्रतिशत अधिक थी।

इस्पात मंत्रालय ने पीएम गतिशक्ति के तहत 38 परियोजनाएं चिह्नित कीं

नयी दिल्ली। इस्पात मंत्रालय ने पीएम गतिशक्ति अभियान के तहत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने एवं ढांचागत फासले को दूर करने के लिए 38 उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाएं चिह्नित की हैं।

मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। इसके मुताबिक, पीएम गतिशक्ति के पोर्टल पर अब इस्पात मंत्रालय की भी मौजूदगी हो गई है। ढांचागत विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर, 2021 में पीएम गतिशक्ति अभियान की शुरुआत की थी। इसके जरिये ढांचागत विकास से जुड़े सभी मंत्रालयों एवं विभागों को एक मंच पर लाकर एकीकृत योजना बनाने और समन्वय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में इस्पात मंत्रालय ने भी अपने प्रशासकीय नियंत्रण वाले सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के इस्पात संयंत्रों से जुड़े विवरण को पीएम गतिशक्ति के पोर्टल पर 'अपलोड' कर दिया है। इसके अलावा इन केंद्रीय उपक्रमों के स्वामित्व वाली सभी खदानों की भू-स्थिति को भी अपलोड किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

इस पोर्टल का संचालन करने वाले बिसाग-एन ने एक एप्लिकेशन बनाया है जिसकी मदद से इस्पात मंत्रालय की देश में सक्रिय 2,000 से अधिक इस्पात संयंत्रों की भू-स्थिति को पोर्टल पर अपलोड करने की योजना है। इन संयंत्रों की भौगोलिक स्थिति के अलावा उनकी उत्पादन क्षमता एवं बनाए जाने वाले उत्पादों की जानकारी भी दर्ज किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही मंत्रालय ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने और ढांचागत अंतराल दूर करने में मददगार 38 परियोजनाओं की भी पहचान की है। पीएम गतिशक्ति अभियान के तहत रेलमार्गों के विस्तार, सड़कों, बंदरगाहों एवं नए अंतर्देशीय जलमार्गों के निर्माण के अलावा गैस पाइपलाइन बिछाने और हवाईअड्डों के निर्माण से इस्पात क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

जी-7 देश खाद्य सुरक्षा के लिए 4.5 अरब डॉलर खर्च करेंगे

एल्माउ (जर्मनी)। एजेंसी

विकसित देशों के संगठन जी-7 के नेताओं ने अनाज एवं अन्य खाद्य उत्पादों की बढ़ती कीमतों के बीच दुनियाभर में खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने पर 4.5 अरब डॉलर खर्च करने पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरफ से 2.76 अरब डॉलर का अंशदान करेगा।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से दुनियाभर में खाद्यान्नों के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा अन्य खाद्य उत्पादों की लागत भी पिछले कुछ महीनों में बड़ी तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह से दुनिया की बड़ी आबादी की खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। बर्लिन से सटे एल्माउ में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 4.5 अरब डॉलर खर्च करने पर सहमति बनी। इस कोष का इस्तेमाल 47 देशों एवं क्षेत्रीय संगठनों को खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण से निपटने में किया जाएगा।

व्हाइट हाउस के मुताबिक, इस राशि का सर्वाधिक इस्तेमाल अफ्रीका महाद्वीप के 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' इलाके के देशों को खाद्यान्न मुहैया कराने में किया जाएगा। यह इलाका लगातार चौथे साल अकाल का सामना कर रहा है जिसकी वजह से दो करोड़ लोगों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया है।

अमेरिका ने इस स्थिति के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, ''उनके कदमों ने खाद्य एवं कृषि उत्पादन को संकुचित कर दिया है। इस दौरान भोजन का इस्तेमाल हथियार के एक औजार के तौर पर किया गया है।''

आरबीआई ने टोकन व्यवस्था की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ाया

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को 'कार्ड-ऑन-फाइल' (सीओडी) टोकन व्यवस्था की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 कर दिया। यह समयसीमा पहले 30 जून, 2022 थी। उद्योग निकायों से प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदन को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह निर्णय किया है। पहले भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कार्ड का ब्योरा भुगतान प्रणाली एवं प्रतिष्ठान के पास सुरक्षित रख लिया जाता था ताकि भावी लेनदेन के समय इस ब्योरे का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इससे कार्ड उपभोक्ताओं का ब्योरा असुरक्षित हाथों में जाने की आशंका रहती थी। इसी पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन व्यवस्था लागू करने को कहा है। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि उद्योग ने व्यवस्था को लागू करने को लेकर कुछ समस्याएं बतायी है। आरबीआई ने कहा, ''इन मुद्दों को हितधारकों के परामर्श से निपटाया जा रहा है और कार्डधारकों को व्यवधान और असुविधा से बचाने के लिए टोकन व्यवस्था की समय सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।''

भारत को 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के लिये 1,15,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत: रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत को 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य हासिल करने के लिये 1,15,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता तथा 50 अरब लीटर खनिज-मुक्त जलापूर्ति की जरूरत होगी। ईवाई इंडिया-एसईडी फंड की रिपोर्ट में यह कहा गया है। बयान के अनुसार, इस दशक में औद्योगिक कच्चे माल के उपयोग के रूप में हरित हाइड्रोजन की मांग बढ़ेगी।

उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बेंगलुरु में आयोजित सम्मेलन में 'हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को गति' शीर्षक से ईवाई-एसईडी फंड की रिपोर्ट के अनुसार हरित और 'ग्रे हाइड्रोजन' उत्पादन के बीच मूल्य समानता बदलाव की गति और पैमाने का निर्धारण करेगी।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिये 1,15,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता तथा 50 अरब खनिज मुक्त जलापूर्ति की जरूरत होगी। देश में मई, 2022 की स्थिति के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1,13,000 मेगावॉट थी। ई वाई इंडिया में भागीदार और राष्ट्रीय प्रमुख (बिजली और यूटिलिटी) सोमेश कुमार ने कहा, ''कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर जारी संकट इस बात की याद दिलाते हैं कि ऊर्जा आयात और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ी अन्य वस्तुओं पर भारत की निर्भरता कैसे उसके रणनीतिक हितों को खतरे में डाल सकती है। औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिये निम्न कार्बन युक्त हरित हाइड्रोजन देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता को लेकर एक वरदान की तरह है।''

रिपोर्ट के अनुसार, हरित हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण (एलसीओएच) की लागत वर्तमान में 400 रुपये प्रति किलो है। इसमें लगभग 40-50 प्रतिशत हिस्सेदारी नवीकरणीय ऊर्जा बिजली संयंत्र तथा 30 से 40 प्रतिशत इलेक्ट्रोलाइज स्टैक की है। इसके अलावा खनिज मुक्त जलापूर्ति समेत अन्य लागत 20 से 30 प्रतिशत है। एसईडी फंड के उपनिदेशक शिवराम कृष्णमूर्ति ने कहा, ''ऊर्जा-गहन उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन मुक्त करने का मामला हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला की प्रतिस्पर्धी क्षमता और अनुकूल नीति पर निर्भर है। हाल ही में अधिसूचित हरित हाइड्रोजन नीति को लागू करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है...।''

एक जुलाई से बैन हो रही प्लास्टिक स्ट्रॉ, जानिए अमूल, फ्रूटी और रियल अब किन विकल्पों पर कर रहे काम

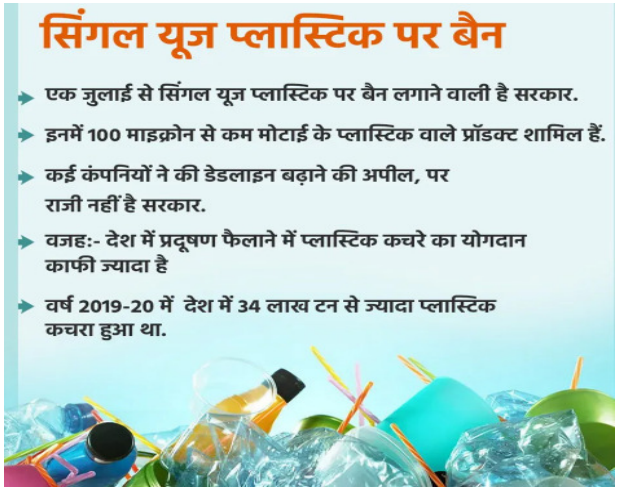

नई दिल्ली । एजेंसी

एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पाद बैन होने जा रहे हैं। इन वस्तुओं में प्लास्ट्रिक स्ट्रॉ भी शामिल है। ठेले पर मिलने वाले ज्यूस से लेकर पैकेज्ड पेय पदार्थों में प्लास्टिक स्ट्रॉ काम आती है। इससे कई कंपनियों के सामने प्लास्टिक स्ट्रॉ का विकल्प निकालने की चुनौती पैदा हो गई है। कई कंपनियां सरकार की इस पहल का विरोध कर रही थीं। लेकिन अब सरकार के सख्त रुख के बाद कंपनियां इस फैसले के साथ खड़ी रहती दिखाई दे रही हैं। शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। इसके साथ ही रियल ब्रैंड के तहत ज्यूस बेचने वाले एफएमसीजी दिग्गज डाबर ने कहा कि वह नियमों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पेक पेपर स्ट्रॉ के साथ आएं।

वहीं, जीसीएमएमएफ के एमडी आर एस सोढ़ी, जिन्हें हर दिन 10-12 लाख स्ट्रॉ की आवश्यकता होती है, ने कहा कि शिपमेंट में थोड़ी देरी के बावजूद संगठन विकल्पों के साथ तैयार है। सोढ़ी ने कहा, 'वर्तमान में हम बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉ के निर्माण पर काम कर रहे हैं, जो पेपर स्ट्रॉ से सस्ती है।'

फ्रूटी ने कहा पड़ेगा लागत पर असर

इसी तरह फ्रूटी बनाने वाली कंपनी पारले एग्रो ने कहा कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन से उसकी बिक्री प्रभावित नहीं होगी। पारले एग्रो की सीईओ शौना चौहान ने टीओआई को बताया, 'बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉ शिपिंग के कारण कंपनी की लागत पर असर पड़ेगा।'

कंपनियों ने दिया था यह तर्क

बेवरेज कंपनियों की जोरदार पैरवी के बीच सरकार ने प्रतिबंध में देरी करने से इनकार किया है। बैन पर रोक लगाने की मांग के साथ कंपनियों ने तर्क दिया था कि भारत में पेपर स्ट्रॉ की आपूर्ति कम थी और उच्च लागत पर उनके आयात से संचालन प्रभावित होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की पीएलआई योजना के तहत 15 और फर्मों का चयन

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने मंगलवार को कहा कि अडाणी कॉपर ट्यूब्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और विप्रो एंटरप्राइजेज सहित 15 फर्मों को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत लाभार्थी के तौर पर चुना गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इन कंपनियों ने कुल मिलाकर 1,368 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है और इनका चयन अभी अस्थाई रूप से है। पिछले साल नवंबर में डायकिन, पैनासोनिक, सिस्का और हैवल्स सहित 42 फर्मों को इस योजना के पहले चरण में चुना गया था जिन्होंने 4,614 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी। व्हाइट गुड्स श्रेणी के तहत एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शामिल हैं।

सरकार ने इस साल मार्च में अधिक खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए अपनी 6,238 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना फिर से खोली थी। दूसरे दौर में कुल 19 कंपनियों ने आवेदन किया था।उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने इस बारे में संवाददाताओं को बताया कि पीएलआई योजना के चलते इन खंडों में घरेलू मूल्यवर्धन मौजूदा 15-20 प्रतिशत से बढ़कर 75-80 प्रतिशत तक होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि इस योजना और अन्य नियामक उपायों ने एयर कंडीशनर तथा एलईडी उत्पादों के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को तेजी से बढ़ावा दिया है। मंत्रालय ने कहा, "दूसरे दौर में प्राप्त 19 आवेदनों के मूल्यांकन के बाद, 1,368 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखने वाले 15 आवेदकों को अस्थायी तौर पर लाभार्थी के रूप में चुना गया है।" इसमें छह कंपनियों ने एयर कंडीशनर कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए 908 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। दूसरी ओर नौ कंपनियां 460 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एलईडी लाइट घटकों का विनिर्माण करेंगी। इन 15 कंपनियों ने पांच वर्षों में कुल 25,583 करोड़ रुपये के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है जिससे करीब 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

राजमार्गों के किनारे हरियाली सुनिश्चित करेगा एनएचएआई

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राजमार्गों के किनारे हरियाली सुनिश्चित करने के लिए अपना 'पेड़ बैंक' खोलेगा। उन्होंने इस दौरान सड़कों के किनारे पौधरोपण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। गडकरी ने कहा कि जब भी निर्माण के लिए एक पेड़ को काटा जाएगा, तो उसकी जगह पांच पौधे लगाए जाएंगे।

उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार के दौरान कहा कि पेड़ों को बचाने के लिए नए-नए तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो सड़कों के निर्माण में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2024 इस आंकड़े को 50 प्रतिशत तक कम करने का प्रयास किया जाएगा।

शरीर में सामान छिपाकर ले जाने वालों के लिए फुल बॉडी स्केनर

दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हुई नई व्यवस्था

नई दिल्ली। एजेंसी

शरीर में सामान छिपाकर ले जाने वालों की खैर नहीं है। दिल्ली इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी ॐ ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर फुल बॉडी स्कैनर का ट्रायल शुरू कर दिया है। अभी यह व्यवस्था दुनिया के कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर ही उपलब्ध है। फुल बॉडी स्कैनर से शरीर में छिपाए गए नॉन-मेटल ऑब्जेक्ट्स भी पकड़ में आ जाते हैं। परंपरागत रूप से इस्तेमाल होने वाले डूर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (ॐ) में ऐसी चीजों को पकड़ना मुश्किल होता है। फुल बॉडी स्कैनर एक ऐसा डेवाइस होता है जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट या पैसेंजर की प्राइवेसी का उल्लंघन किए बिना शरीर में छिपाई गई चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

डायल की ऑपरेटिंग कंपनी जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मुताबिक ट्रायल के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक एरिया में फुल बॉडी स्कैनर लगाया गया है। यह ट्रायल रियल टाइम बेसिस में होगा। यानी पैसेंजर को सिक्योरिटी चेक के दौरान इस मशीन से गुजरना होगा। यह रिटल टाइम ट्रायल 45 से 60 दिन तक होगा। इस दौरान सभी स्टेकहोल्डर्स यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, सीआईएसएफ, डायल और पैसेंजरों के फीडबैक लिया जाएगा। ट्रायल के बाद इसके नतीजों को रेगुलेटरी संस्थाओं के साथ साझा किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रियल टाइम बेसिस पर ट्रायल

डायल की ऑपरेटिंग कंपनी जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मुताबिक ट्रायल के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक एरिया में फुल बॉडी स्कैनर लगाया गया है। यह ट्रायल रियल टाइम बेसिस में होगा। यानी पैसेंजर को सिक्योरिटी चेक के दौरान इस मशीन से गुजरना होगा। यह रिटल टाइम ट्रायल 45 से 60 दिन तक होगा। इस दौरान सभी स्टेकहोल्डर्स यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, सीआईएसएफ, डायल और पैसेंजरों के फीडबैक लिया जाएगा। ट्रायल के बाद इसके नतीजों को रेगुलेटरी संस्थाओं के साथ साझा किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्या है इसकी खूबी

दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाया गया नया एडवांस्ड बेस्ड स्कैनर एक मिलीमीटर वेव बेस्ड स्कैनर है जो बहुत सटीक है। साथ ही इसमें हेल्थ रिस्क नहीं है और लोगों की निजता का पूरा ध्यान रखा गया है। इससे गुजरने पर यात्री के कपड़ों में छिपे किसी भी सामान की जानकारी मिल जाएगी। इससे यात्रियों को कपड़े उतारने की समस्या से मुक्ति मिलेगी और सुरक्षाकर्मियों के लिए भी आसानी होगी। साथ ही सुरक्षा जांच में भी कम समय लगेगा।

क्या होती है फुल बॉडी स्कैनर

असल में फुल बॉडी स्कैनर ऐसी मशीन होती है जो किसी भी शख्स के पूरे शरीर को स्कैन कर एक डिजिटल इमेज बना देती है। इससे कंप्यूटर में देखकर ये पता लग जाता है कि उसने अपने कपड़े के पीछे कुछ छिपाया तो नहीं है। पहले शख्स को मशीन के अंदर खड़ा होना होता है। फुल बॉडी स्कैनर की मशीन शरीर पर तरंगें फेंकती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक्स-रे किया जाता है। तरंगों की मदद से पूरे शरीर की एक डिजिटल इमेज तैयार होती है। इसे सुरक्षाकर्मी कंप्यूटर में देखते हैं।

क्या है विवाद

हालांकि इसे लेकर पूरी दुनिया में एक राय नहीं है। दुनिया के कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स में ही इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यूरोप में इसका इस्तेमाल बैन है। इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इससे प्राइवेसी का उल्लंघन होना है। फुल बॉडी स्कैन से जो डिजिटल इमेज बनती है, वह बिना कपड़ों के ली गई तस्वीर जैसी दिखती है। इसे लेकर कई संगठनों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि अब तकनीक में कई बदलाव किए गए हैं। अब इससे बनने वाली डिजिटल इमेज पुतले जैसी दिखती है।

गुप्त नवरात्र : घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत नियम

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

गुप्त नवरात्र 30जून से प्रारम्भ हो रही है। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुप्त नवरात्रि तंत्र-मंत्र को सिद्ध करने वाली माना जाता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक महाविद्याओं को भी सिद्ध करने के लिए मां दुर्गा की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, मां धूम्रवती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है।

गुप्त नवरात्रि 30.6.2022 तिथि और घट स्थापना शुभ मुहूर्तः-

प्रातः- 6 से 7:30 शुभ
दोः- 12 से 3:40 (अभिजीत,लाभ,अमृत)
सन्ध्याः- 5:30 से 8 (शुभ,अमृत)
रात्रि साधना 11:30 से 2
नवरात्रि शुरू 30-6- 2022
नवरात्रि समाप्त 8-7-2022

गुप्त नवरात्रि में प्रयोग में आने वाली सामग्री

मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप,वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन-चूड़ी, सुगंधित तेल, बंदनवार आम के पत्तों का, लाल पुष्प, दूर्वा, मेंहदी, बिंदी, सुपारी साबुत, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंदनवार, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफेद और पीली, गंगाजल आदि।

मां दुर्गा की गुप्त नवरात्रि में ऐसे करें पूजा

1. गुप्त नवरात्रि के दौरान आधी रात को मां दुर्गा की पूजा की जाती हैं।
2. मां दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और चुनरी अर्पित करें।
3. इसके बाद मां दुर्गा के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित करें।
4. मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है।
5. सरसों के तेल से दीपक जलाकर 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का जाप करना चाहिए।

दुर्गा सप्तशती का ऐसे करें पाठ

1. दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
2. दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सबसे पहले स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए।
3. बैठने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए, अगर आपके पास कुशा का आसन नहीं है तो ऊन के बने हुए आसन का प्रयोग कर सकते हैं।
4. पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी एवं सभी देवगणों को प्रणाम करें। माथे पर चंदन या रोली का तिलक लगाएं।
5. लाल पुष्प, अक्षत एवं जल मां को अर्पित करते हुए पाठ का संकल्प लें।
6. इसके बाद पाठ को आरंभ करने से पहले उत्कीलन मंत्र का जापकरें। इस मंत्र को आरंभ और अंत में 21 बार जप करना चाहिए।
7. इसके बाद मां दुर्गा का ध्यान करते हुए पाठ का आरंभ करें। इस तरह से मां दुर्गा सप्तशती का पाठ करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।

मनोकामना अनुसार मन्त्र प्रयोग

पति प्राप्ति के लिये मन्त्र

कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरि !
नंदगोपसुतम् देवि पतिम् मे कुरुते नमः!!

यह मंत्र दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ किसी योग्य ब्राहमण से करवाऐ माता से प्रार्थना करें हे माँ मै आपकी शरण में आ गयी मुझे शीघ्र अति शीघ्र सौभाग्य की प्राप्ति हो और मेरी मनोकामना शीघ्र पुरी हो माँ भगवती कि कृपा से अवश्य सफलता प्राप्त होगी।

पत्नी प्राप्ति के मंत्र

पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानु सारिणीम्।
तारिणींदुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम.!!

माँ दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ किसी योग्य ब्राह्मण से करवाऐ आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी.!!

शत्रु पर विजय ओर शांति प्राप्ति के लिए
सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि।
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्.!!
बाधा मुक्ति एवं धन-पुत्रादि प्राप्ति के लिएः
सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन-धान्य सुतान्वितः।
मनुष्यों मत्प्रसादेन भवष्यति न संशय..!!
शत्रु का नाश, भय से शांति के लिए बगलामुखी अनुष्ठान
ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचं मुखम पदम् स्तम्भय। जिव्हां कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा।।

---

30 जून से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि, जरूर जानें ये ज़रूरी बातें

श्री रघुनंदन जी
9009369396
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तविद अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट

चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारें में तो हर कोई जानता है। लेकिन आपको बता दें इसके अलावा भी साल में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती हैं जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जो कि माघ और आषाढ़ के महीने में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारें में तो हर कोई जानता है। लेकिन आपको बता दें इसके अलावा भी साल में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती हैं जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जो कि माघ और आषाढ़ के महीने में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के उपासक गुप्त तरीके से पूजा उपासना करते हैं। आषाढ़ माह में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि का प्रारम्भ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। इस साल 2022 में पहली गुप्त नवरात्रि का प्रारम्भ 30 जून से शुरू होगा, जिसका समापन 8 जुलाई को होगा। बता दें इसी दिन से ही 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इसके अलावा इस बार गुप्त नवरात्रि पर शुभ संयोग भी पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं 30 जून को शुरू होने वाली गुप्त नवरात्रि के शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग व घट स्थापना के बारें में-

सबसे पहले आपको बता दें, गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जून को हो रही है। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 26 मिनट से लेकर 06 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। ऐसे में इस समय पर की गई घटस्थापना शुभ फल देती है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानि 30 जून को विशेष संयोग बन रहा है। जिस वजह से इस दिन की गई पूजा का फल शुभ रहने वाला है। बता दें, इस दिन एक साथ गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, अडाल योग और विडाल योग बन रहे हैं। साथ ही पुष्य नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। एक साथ इतने शुभ मुहूर्त बनना बेहद शुभ होता है।. इस शुभ मुहूर्त में यदि आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें अवश्य सफलता मिलती है।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घटस्थापना भी शारदीय नवरात्रि की तरह ही की जाती है। आषाढ़ नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह और शाम मां दुर्गा की पूजा-आरती जाती है। साथ ही इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। माता को बाताशे और लौंग का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा पूजा के दौरान मां दुर्गा के मंत्रों का जाप किया जाता है।

आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के नौ दिनों में आपको प्रातः काल स्नान करने के बाद मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हुए मां दुर्गा के विशेष मंत्र-

'विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि' का जाप करना चाहिए।

जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश या किसी मनोकामना की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान रोज सुबह स्नान के बाद 'ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना' मंत्र का जाप करें। ज्योतिष शास्त्री बताते हैं कि अगर इस विधि से अगर मां का पूजन करते हैं तो आपको हर काम में सफलता मिलती है।

आषाढ़ नवरात्रि के नियम

इस गुप्त नवरात्रि के दौरान सिद्धि पाने के लिए मंत्र जाप, पूजा-पाठ, हवन और साधना गुप्त रूप से करने का विधान है। इसलिए इन दिनों में ज्यादातर समय घर पर ही रहा जाता है। इस समय साफ-सफाई पर आम दिनों से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। गुप्त नवरात्र में पानी उबालकर पिया जाता है। अन्न नहीं खाया जाता। सिर्फ रसीले फल खाते हैं। इन दिनों में जो लोग साधना और पूजा-पाठ नहीं करते वो भी मसालेदार और तली, भुनी चीजों से परहेज रखते हैं या कम ही खाते हैं। देवी साधना करने वालों को दिन में सोने की मनाही होती है। इसलिए गुप्त नवरात्र में सिर्फ रात में ही सोते हैं। इन बातों का ध्यान रखने से सेहत अच्छी रहती है और साधना भी सफल होती है।

नवरात्रि के दौरान क्या करें

आयुर्वेद के मुताबिक आषाढ़ नवरात्रि के दौरान नीम, लौंग, दालचीनी और हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इनके साथ ही त्रिफला चूर्ण को गरम पानी के साथ लेना चाहिए और गिलोय भी खाना चाहिए। वहीं, इन दिनों टमाटर, अचार, दही और अन्य खट्टी चीजें खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्रत-उपवास के दौरान शारीरिक परेशानी नहीं होती।

MP Breaking News के इंदौर संभागीय कार्यालय का शुभारंभ

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने फीता काट कर किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मप्र के सबसे बडे न्यूज पोर्टल के संभागीय कार्यालय का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोज मनु भी उपस्थित थे। इंदौर के सांवेर रोड क्षेत्र में स्थापित इस कार्यालय से इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों की खबरें प्रेषित की जाएगी।

MP Breaking News के संभागीय कार्यालय का शुभारंभ 28 जून को इंदौर में हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि श्री कैलाश विजयवर्गीय और विशिष्ट अतिथि श्री मनोज मनु ने फीता काट कर कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता MP Breaking News के संस्थापक श्री वीरेंद्र शर्मा ने की। अतिथियों ने कार्यालय में देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि श्री विजयवर्गीय ने लैपटॉप का बटन दबा कर पहली न्यूज भी पोर्टल पर लांच की।

एमपी ब्रेकिंग के संभागीय कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर उन्होने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि टीवी और प्रिंट मीडिया के बाद अब इंटरनेट मीडिया का दौर है। इसे टीवी के बजाय कम्प्यूटर और मोबाइल पर ही देखा जा सकता है। शुभारंभ कार्यक्रम में MP Breaking News के संपादक श्री गौरव शर्मा, सीईओ सुश्री श्रुति कुशवाह, न्यूज डायरेक्टर श्री सचिन बंसल सहित इंदौर के विभिन्न सामाजिक और औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी, उद्योगपति और पत्रकार उपस्थित थे।

हिमालया वैलनेस कंपनी का नया ईक्विटी कैम्पेन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के अग्रणी वैलनेस ब्रांड्स में से एक, हिमालया वैलनेस कंपनी ने एक नया ईक्विटी कैम्पेन लॉन्च किया है, जो हर आयु समूह के लोगों को सेहत व स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह कैम्पेन ''वैलनेस इन एवरी होम, हैप्पीनेस इन एवरी हार्ट'' (हर घर में सेहत, हर दिल में खुशी) के हिमालया के उद्देश्य को जीवंत करता है। पिछले नौ दशकों में हिमालया सेहत व स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, जो पूरी दुनिया के ग्राहक चाहते हैं। हिमालया का मानना है कि यदि हर व्यक्ति अपनी सेहत और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा, तो दुनिया में खुशी बढ़ जाएगी। इस नए कैम्पेन में हमारी जीवनशैली में हुए परिवर्तन और अच्छी सेहत व स्वास्थ्य के लिए प्रिवेंटिव हैल्थकेयर के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस नए अभियान के बारे में, श्री राजेश कृष्णमूर्ति, बिज़नेस डायरेक्टर - कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीज़न, हिमालया वैलनेस कंपनी ने कहा, '' हिमालया में हमारा मानना है कि सेहत में ही असली खुशी है। इस ब्रांड फिल्म स्वस्थ व प्रसन्न जीवन के लिए सेहत के महत्व के प्रति जागरुकता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है। हिमालया ने ग्राहकों के लिए सिर से पैर तक संपूर्ण देखभाल करने के लिए अनेक उत्पादों का अन्वेषण व विकास किया है, जिससे हर घर में सेहत, हर दिल में खुशी पहुँचाने का हमारा उद्देश्य प्रदर्शित होता है। '' श्री दामोदरन नायर, प्रेसिडेंट एवं हेड ऑफ ऑफिस (एफसीबी बैंगलोर) ने कहा, '' पिछले कुछ सालों में हम सभी ने स्वास्थ्य और सेहत के महत्व को किसी न किसी रूप में जाना है। हिमालया जैसे ब्रांड के लिए यह समय सही है, जब यह सेहत का प्रणेता बन अपनी 90 सालों से ज्यादा समय की विरासत स्थापित कर रहा है और हमारे दैनिक जीवन में स्वास्थ्य की भूमिका पर बल दे रहा है। एक पुरानी कहावत 'स्वास्थ्य ही संपत्ति है' आज के समय के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, और हिमालय इससे एक कदम आगे बढ़कर कह रहा है, ''सेहत ही असली खुशी है''।

डीज़ो ने अपना पहला हाफ-इन-ईयर टीडब्लूएस डीज़ो बड्स पी लॉन्च किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

रियलमी टेकलाईफ ईकोसिस्टम के तहत पहले ब्रांड, डीज़ो ने आज 40 घंटे के म्यूज़िक प्लेबैक और फास्ट चार्जिंग क्षमता के साथ अपने पहले हाफ-इन-ईयर टीडब्लूएस ईयरबड्स, डीज़ो बड्स पी लॉन्च किए। ये टीडब्लूएस ईयरबड लाईटवेट और आरामदायक हैं और यूज़र्स की सुविधा के लिए कॉम्पैक्ट चार्जिंग केस के साथ आते हैं, ताकि इन्हें कहीं भी आसानी से लेकर जाया जा सके। खूबसूरत डिज़ाईन के ये ईयरबड टच कंट्रोल पर तीन डॉट प्रदर्शित करते हैं, जो टच गैस्चर्स का इस्तेमाल आसान बनाने के अलावा इसका आकर्षण भी बढ़ाते हैं। डीज़ो बड्स पी का हर ईयरबड कागज से भी हल्का है और वजन में केवल 3.5 ग्राम है, इसलिए इसे लंबे समय तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है तीन आकर्षक रंगों डायनैमो ब्लैक, मार्बल व्हाईट, और ऐडी ब्लू में उपलब्ध इस ईयरबड में संगीतप्रेमियों और गेमिंग के शौकीनों के लिए बेस बूस्टर एलगोरिद्म के साथ 13 मिमी का विशाल ड्राईवर, पीयूएपीक डायफ्राम, 88मिलीसेकंड की सुपर लो लेटेंसी है।

सोनी इंडिया की तीन स्टैंडआउट वाइड-एंगल ई-माउंट एपीएस -सी लेंस की घोषणा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

पावर ज़ूम जी लेंस ई पीजेड 10-20mm एफ 4 जी (मॉडल SELP1020G), बहुमुखी जी लेंस ई 15एमएम एफ 1.4 जी (मॉडल SEL15F14G), और अल्ट्रा-वाइड प्राइम ई 11एमएम एफ 1.8 (मॉडल SEL11F18) के साथ अब सोनी ने अपनी लेंस लाइन का विस्तार किया है, जिससे ई-माउंट लेंस की कुल संख्या 70 हो गई है।

यह पहला नया लेंस, ई पीजेड 10-20mm एफ 4 जी दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हल्का, अल्ट्रा-वाइड एंगल कॉन्स्टेंट एफ4 एपीएस -सी पावर-ज़ूम लेंस है। असाधारण जी लेंस इमेजरी, त्रुटिहीन ऑटोफ़ोकस (एएफ) प्रदर्शन, और बहुमुखी पावर-ज़ूम एक साथ इस कॉम्पैक्ट ज़ूम लेंस को फ़िल्मों के साथ चित्रों के लिए भी रिफ़ाइंड दृश्य अभिव्यक्ति और संचालन क्षमता प्रदान करता है। यह ई 15एमएम एफ 1.4 जी (35mm फ़ुल-फ़्रेम के समानः 22.5 mm) विशाल रचनात्मक

क्षमता वाले बहुमुखी एपीएस -सी लेंस में सुंदर एफ 1.4 बोकेह के साथ शानदार जी लेंस रिज़ॉल्यूशन होता है। यह कॉम्पैक्ट और हल्का प्राइम लेंस गतिशील इमेजरी, उत्कृष्ट एएफ और नियंत्रण देता है और उच्च संचालन क्षमता के साथ चित्रों और फ़िल्मों दोनों के लिए उत्तम है। बड़ा अपर्चर, अल्ट्रा-वाइड एपीएस -सी प्राइम, ई 11एमएम एफ 1.8 (35mm फ़ुल-फ़्रेम के समानः 16.5 mm) देता है, असाधारण कोने-से-कोने तक का रिज़ॉल्यूशन, शानदार बोकेह, अत्यधिक अभिव्यक्ति और आश्चर्यजनक सेल्फ़ी के लिए तेज़, विश्वसनीय एएफ । यह कॉम्पैक्ट और हल्का है, इसलिए एक बार में व्लॉगिंग और वीडियो शूट करने के लिए एकदम सही है। 'सभी तीन नए लेंअ अपने में असाधारण हैं। सोनी ने वर्षों के अनुभव, अनुसंधान और व्यापक लेंस डिज़ाइन को मिलाकर यह सुनिश्चित किया है कि ई पीजेड 10-20mm एफ4 जी एक उल्लेखनीय पावर ज़ूम जी लेंस है जो एक असाधारण प्रदर्शन और हैंडलिंग प्रदान करता है', मुकेश श्रीवास्तव, सोनी इंडिया में हेड डिजिटल इमेजिंग बिजनेस, ने कहा। 'शानदार बोकेह और उत्कृष्ट ऑटोफ़ोकस क्षमताओं से, ई 15एमएम एफ 1 .4 जी निश्चित रूप से कंटेंट क्रिएटर्स का पसंदीदा बन जाएगा और फ़िल्मों की शूटिंग के लिए अनुकूलित इसकी विशेषताओं के साथ कॉम्पैक्ट और हल्का ई 11एमएम एफ 1.8 व्लॉगिंग के लिए आदर्श लेंस है'।

आकाश अंबानी के बाद ईशा को मिलेगी अहम जिम्मेदारी

मुकेश अंबानी बेटी को सौंप सकते हैं रिटेल बिजनस की कमान

नई दिल्ली। एजेंसी

एशिया और भारत के दूसरे सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी ने अपनी उत्तराधिकार योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके पहले चरण में उन्होंने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले चरण में मुकेश अंबानी अपनी बेटी ईशा को रिलायंस की रिटेल यूनिट की कमान दे सकते हैं। साथ ही 27 साल के अनंत अंबानी को ग्रीन एनर्जी बिजनस का जिम्मा सौंपा जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक 30 साल की ईशा को रिटेल बिजनस का चेयरमैन बनाने की घोषणा जल्दी ही हो सकती है। अभी वह रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। हालांकि रिलायंस ग्रुप के एक प्रतिनिधि ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो 217 अरब डॉलर के कारोबार वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा हैं। यह देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है और मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

इससे पहले मंगलवार को आकाश अंबानी को रिलायंस जियो

इन्फोकॉम लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया था। ईशा और आकाश उस टीम का हिस्सा थे जिसने कंपनी में मेटा प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक) के निवेश में अहम भूमिका निभाई थी। ईशा ने येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इसके बाद ईशा ने आगे की पढ़ाई कैलिफोर्निया की स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। यहां से उन्होंने एमबीए की डिग्री ली है। ईशा कुछ दिनों तक McKinsey and Company में बिजनस एनालिस्ट के तौर पर काम कर चुकीं हैं। ईशा साल 2015 में वह फैमिली बिजनस में शामिल हुई थीं। वह जियो प्लेटफॉर्म्स, जियो लिमिटेड के बोर्ड में भी शामिल हैं।

रिलायंस का रिटेल बिजनस

रिलायंस रिटेल देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। कंपनी के वित्तीय परिणामों के मुताबिक रिलायंस रिटेल का स्टाफ 70 फीसदी बढ़ कर 3 लाख 61 हजार हो गया है। रिटेल और अन्य बिजनस में कुल मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2 लाख 10 हजार नई नौकरियां दी हैं। पिछले वित्त वर्ष में रिलायंस रिटेल ने रोजाना करीब 7 नए स्टोर्स के हिसाब से कुल 2500 से अधिक स्टोर्स खोले। सिर्फ पिछली तिमाही में ही कंपनी ने 793 नए स्टोर्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं। कंपनी के स्टोर्स की कुल संख्या 15 हजार के पार पहुंच गई है। स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलायंस रिटेल के रजिस्टर्ड ग्राहकों की संख्या 19 करोड़ 30 लाख के पार जा पहुंची है।

मारवाड़ी यूनिवर्सिटी ने 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए शुरू की प्रवेश प्रक्रिया

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

गुजरात सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) का दर्जा पाने वाले गुजरात के सबसे युवा विश्वविद्यालय, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अपनी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत इच्छुक विद्यार्थी साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लॉ, आर्ट, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और रिसर्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

स्नातक स्तर पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आईटी, आईसीटी, कंप्यूटर, केमिकल और ऑटोमोबाइल में बी.टेक, बी.एससी, बीबीए, बी.कॉम, बी.कॉम एलएलबी ऑनर्स, बीए एलएलबी ऑनर्स, एलएलएम, बीसीए, बी.एससी, आईटी, बी.फार्म, बी. फिजियोथेरेपी, और बी.एससी. ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए प्रवेश जारी है। स्नातकोत्तर स्तर पर, विद्यार्थी मैकेनिकल, सिविल, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, सीएडी/सीएएम, थर्मल, आईसीटी, कंप्यूटर,जियो टेक, स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल - इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ड्राइव जैसे विषयों में एम.टेक, माइक्रोबायोलॉजी,बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री,फिजिक्स, मैथ्स और एनवायरमेंट साइंस में एमएससी;

साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ में एमएससी ; एमबीए और एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इंजीनियरिंग जैसे नए प्रोग्राम के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया जारी है, यह एक तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसमें 2019 में 53.2 मिलियन रोजगार मिलने के बाद अब 2023 में 62 मिलियन के रोजगार के अवसर मिलने अनुमान हैं।

मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के डॉ संदीप संचेती ने कहा, 'हमें भविष्य के लिए तैयार स्मार्ट लोगों की वर्कफोर्स बनाने पर गर्व है, जो न केवल अपने क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम है, बल्कि वे लीडर बनने और अपने चुने हुए क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने में भी समर्थ हैं। पढ़ाने और सीखने के खास तरीके; इनोवेशन की संस्कृति, परिसर की विविधता, वाइब्रेंट कैम्पस लाइफ और मजबूत इंडस्ट्री-एकेडेमिक कनेक्शन मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की पहचान हैं।'

हाल ही में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से अधिक हुई है, जो संस्था के लिए मील के पत्थर के समान है। इसमें जिसमें 51 देशों के 1500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल हैं। यूनिवर्सिटी में 480 से ज्यादा कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती है, 2021 में ऑन-कैंपस प्लेसमेंट में अमेज़ॅन द्वारा विद्यार्थियों को 34 लाख रुपये का एनुअल सीटीसी का सबसे बड़ा पैकेज दिया गया था। इसके अलावा अदानी, रिलायंस, बायजू, एचएफएफसी, फ्लिपकार्ट, आईसीआईसीआई, सीके और ओला भी यहाँ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के पास संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और पोलैंड में विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए 25 से ज्यादा एफीलिएशन और एमओयू भी हैं। जिन विद्यार्थियों का रुझान एंट्रेप्रेन्योरशीप की ओर है, उनके लिए मारवाड़ी यूनिवर्सिटी ने 58 से अधिक स्टार्टअप शुरू किए हैं, जिन्हें अपने मारवाड़ी यूनिवर्सिटी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन रिसर्च एमयूआईआईआर सेंटर की मदद से 50 लाख रुपये का फंड इकट्ठा कर दिया गया है।

एमएसएमई को ऋण पहुंच सुगम बनाने के प्रयास जारी: सचिव

नयी दिल्ली। एजेंसी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सचिव बी बी स्वैन ने सोमवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्यमियों के लिए ऋण की पहुंच को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रही है। स्वैन ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की तरफ से आयोजित एक शिखर सम्मेलन में कहा कि किफायती ऋण तक पहुंच सभी के लिए एक चुनौती बनी हुई है और इस समस्या के समाधान को लेकर प्रयास किये जा रहे है।सचिव ने कहा, "सस्ते ऋण तक पहुंच सभी के लिए एक चुनौती बनी हुई है.....विशेष रूप से एमएसएमई के लिए। हम इस पहलू को पर्याप्त रूप से हल करने के लिए ऋण तक पहुंच को आसान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।" स्वैन ने कहा, "हम छोटे उद्यमों को भी औपचारिक ढांचे में लाने की दिशा में काम कर रहे हैं।" उन्होंने बताया कि आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत 3.47 लाख करोड़ रुपये की ऋण मंजूर किये गए है। इसमें से 2.31 लाख करोड़ रुपये के ऋण एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए है। इस दौरान एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि मंत्रालय विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई की वास्तविक क्षमता को बाहर लाकर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना चाहता है।

वीपीएन प्रदाताओं के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाई गई

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) ने वीपीएन प्रदाताओं और एमएसएमई के लिए नए साइबर सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी है। डेटा केंद्रों, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (वीपीएस) प्रदाताओं, क्लाउड सेवा प्रदाताओं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवा (वीपीएन सेवा) प्रदाताओं ने इन नियमों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए इन नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाकर 25 सितंबर, 2022 कर दी गई है। इस निर्णय से कंपनियों को राहत मिलेगी और उन्हें नए मानदंडों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय भी मिलेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंगलवार को कहा गया, "सीईआरटी-इन ने एमएसएमई के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों को लागू करने और ग्राहकों/ग्राहकों के विवरण के सत्यापन के लिए की समयसीमा 25 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दी है।" विज्ञप्ति के अनुसार, उद्योग द्वारा निर्देशों को लागू करने के लिए और समय देने का अनुरोध करने के बाद इसकी समयसीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।